www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 303 | जौनपुर बुधवार, 24 जून 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

वियतनाम पहुंचे दो भारतीय युद्धपोत, नौसैनिक सहयोग को मिलेगी नई मजबूती

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय नौसेना के युद्धपोत वियतनाम पहुंच चुके हैं। ये युद्धपोत नौसेना के पूर्वी बेड़े के अंतर्गत संचालित ऑपरेशनल तैनाती के हिस्से के रूप में यहां पहुंचे हैं। नौसेना के अनुसार, छ्ठे उदयगिरि और छ्ठे कवरत्ती 22 जून को वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी स्थित न्हा रोंग बंदरगाह पहुंचे हैं। नौसेना के युद्धपोत स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित हैं। इस नौसैनिक दल का नेतृत्व पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल आलोक आनंद कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस तैनाती में शामिल आईएनएस उदयगिरि एक अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है। वहीं, आईएनएस कवरत्ती की बात करें तो यह पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता से लैस एक उन्नत कोर्वेट है। ये दोनों ही युद्धपोत भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और आत्मनिर्भर नौसैनिक शक्ति का उदाहरण हैं। यहां बंदरगाह प्रवास के दौरान भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी के बीच अनेक पेशेवर गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें सैन्य विशेषज्ञों के बीच विचार–विमर्श, क्रॉस–डेक विजिट, संयुक्त खेल प्रतियोगिताएं तथा सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के वरिष्ठ नौसैनिक अधिकारियों के बीच उच्चस्तरीय बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, सहयोग और साझा हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा की जानी है।

आईएमडी ने मंगलवार को मुंबई में मॉनसून के आगमन की घोषणा की

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा कि 23–26 जून और 29 जून को हरियाणा–चंडीगढ़–दिल्ली और पंजाब में, 23–24 जून और 29 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 23 जून और 28–29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 23–29 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कहीं–कहीं से लेकर छिटपुट बारिश की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, दक्षिण–पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों, तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों, तथा छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2–3 दिनों में दक्षिण–पश्चिम मॉनसून के गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों, और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैंय इसके बाद के 3–4 दिनों में झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसके आगे बढ़ने की संभावना है। इस सप्ताह पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर भारत और उप–हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश (7–20 सेमी) होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, अगले 4–5 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में और अगले 2–3 दिनों में विदर्भ, दक्षिण–पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में लू (हीट वेव) की स्थिति रहने की संभावना है।

भारत में 70 वर्ष से उम्र के हर नागरिक के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध है - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिडिल क्लास हमेशा हमारी बड़ी प्राथमिकता रहा है। इस वर्ग की 'जीवनयापन में सुगमता' के लिए सरकार ने हर स्तर पर काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में मिडिल क्लास परिवारों में एक बड़ा खर्चा डायबिटीज या ऐसी लाइफस्टाइल से जुड़े इलाज का रहता है। जन औषधि केंद्रों पर 80 परसेंट डिस्काउंट पर ऐसी दवाएं मिल रही हैं। अगर आपका पहले हजार रुपया खर्चा होता था, तो आज 200 रुपये में काम हो जाता है, 800 रुपये बच रहा है और इससे बीते वर्षों में करीब 40 हजार करोड़ रुपए की बचत देश के अनेक परिवारों की हुई है। उन्होंने कहा, "मिडिल क्लास के बजट का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्गों के इलाज पर भी जाता है। आज 70 वर्ष से ऊपर के हर नागरिक के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।" सोमवार को नई दिल्ली में एक निजी समाचार चौनल के समिट में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 के बाद, हालात को बदलने के लिए हम राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे बढ़े, हम निकल पड़े। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 साल, मिडिल क्लास के लिए कमाई के साथ–साथ बचत के भी रहे हैं। 2013–14 में, लगभग 2 लाख रुपए तक की आय होने पर टैक्स लगता था, आप सबको वो नसीब रहा होगा। और यह टैक्स मिडिल क्लास देता रहता था। आज 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। यानी टैक्स फ्री इनकम कई गुणा बढ़ गई है। उन्होंने कहा, "ळैज रिफॉर्म्स के कारण भी मिडिल क्लास को बहुत सुविधा हुई है। टैक्स फाइलिंग का समय और खर्चा भी बच गया है। क्योंकि यह बहुत ही आसान हो गया है। घर बैठे ही प्ज्ट फाइल हो रहे हैं, अगर कोई सेटलमेंट का इश्यू है, तो वो फेसलेस हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि साढ़े 9 हजार से अधिक मोबाइल टावर बनाए गए हैं। करीब 45,000 गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाई। नक्सल प्रभावित जिलों में 1800 से अधिक बैंक ब्रांच खोली गई।

राष्ट्रपति मुर्मु आज 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज मंगलवार को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में होने वाले 'सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी–2' में 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार पाने वाले 65 लोगों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। शाम 5 बजे शुरू होने वाले समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी, जिनमें दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण और 56 पद्म श्री शामिल हैं। राष्ट्रपति ने 25 मई को आयोजित पहले नागरिक सम्मान समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे, जिनमें दो पद्म विभूषण, छह पद्म भूषण और 57 पद्म श्री शामिल थे। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, जन–कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा जैसे अलग–अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 'पद्म विभूषण' असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, 'पद्म भूषण' उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए और 'पद्म श्री' किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर की जाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के संस्थापक शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण के लिए चुना गया है।

कतर हादसे में 12 भारतीयों की मौत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया गहरा शोक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए दर्दनाक हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने घटना पर शोक जताया और पीड़ित परिवार के प्रति दुख जाहिर किया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "कतर के रास लफ्फान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए धमाके में भारतीय नागरिकों समेत कई लोगों की मौत और घायल होने से बहुत दुख हुआ। जैसे–जैसे और जानकारी सामने आ रही है, हमारा दूतावास कतर के अधिकारियों के संपर्क में है और इस हादसे से प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवारों की मदद करने की कोशिश कर रही है। हमारी प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं।" कतर के दोहा स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने एक्ब्स पोस्ब्ट में पुष्टि करते हुए बताया, "रविवार रात हुए रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। हम इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कतर के दोहा स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने सोशल मीडध्या प्ल्टेफॉर्म 'एक्ब्स' पोस्ब्ट में पुष्टि करते हुए बताया, "रविवार रात हुए रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है।

बिचौलियों की भूमिका होगी कम, किसानों को मिलेगा पूरा फायदा : अमित शाह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) के ऑक्शन पोर्टल एनएएफईएक्स डॉट इन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 'नाफेड' ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण के रूप में चार पहलों की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि जो नाफेड 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, वह आज 500 करोड़ मुनाफे और 30 हजार करोड़ टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सहायता कर रहा है। 2014 में नाफेड गहरे आर्थिक संकट मे था। नाफेड के अधिकारियों ने पीएम मोदी के साथ बैठक की। इसके बाद भारत सरकार ने आर्थिक मदद करके नाफेड को फिर से मजबूती के साथ चालू किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि उस वक्त मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मुझे पता है कि नाफेड गहरे आर्थिक संकट में था। आने वाले दो वर्षों में सहकारिता मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा दलहन का एक दाना भी व्यापारियों के माध्यम से न आए बल्कि सीधे किसानों के पास से आए। इससे किसानों को सीधा मुनाफा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही दलहन का दाम किसानों तक पहुंचेगा, अपने आप दलहन का रकबा बढ़ने लगेगा और देश एक प्रकार से दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों से सीधे खरीद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है। मेरा मानना है कि नाफेड की ओर से भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करना होगा, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे। अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मेरे जैसे कई भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए 23 जून का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के सूत्र को चरितार्थ और देश को एकजुट रखने के लिए अपना बलिदान दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने प्रसिद्धि के लिए कुछ नहीं किया और उन्होंने जो कुछ किया, उसके दूरगामी परिणाम रहे।

यमुना जल बंटवारे पर तीन दशक पुराना गतिरोध खत्म

हरियाणा, (एजेंसी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में पानी के विभिन्न मुद्दों पर बैठक की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि आज की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोनों मौजूद थे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने 1994 में हुए समझौते के तहत हरियाणा के अतिरिक्त पानी के मुद्दे पर चर्चा की। आज इस बात पर सहमति बनी कि एक नया समझौता किया जाएगा ताकि यह पक्का किया जा सके कि राजस्थान को उतना पानी मिले जितना उसे मूल रूप से समझौते के तहत आवंटित किया गया था। पानी को पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा और दोनों राज्य इस व्यवस्था पर सहमत हो गए हैं। उम्मीद है कि अगले सोमवार तक समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसका आदान–प्रदान होगा। आज इस फैसले को अंतिम रूप दे दिया गया है। सीएम सैनी ने बताया कि बैठक में हरियाणा एवं राजस्थान के मध्य जल वितरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत एवं सकारात्मक चर्चा हुई। हमारा प्रयास है कि संवाद और सहयोग की भावना के साथ जल संसाधनों के न्यायसंगत एवं प्रभावी प्रबंधन की दिशा में सार्थक समाधान सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के प्रयासों से लगातार बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों का मकसद जल प्रबंधन और यह सुनिश्चित करना है कि पानी हर व्यक्ति तक पहुंचे। लखवार, किशाऊ और रेणुका बांध परियोजनाओं पर सहमति बन गई है। इसके परिणामस्वरूप, इन परियोजनाओं से पानी उपलब्ध होगा और राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस पानी को राजस्थान तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। हाल की चर्चाओं में इस बात पर भी सहमति बनी कि मानसून के दौरान बेकार बह जाने वाले बारिश के पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसे इस तरह से निर्देशित किया जाना चाहिए।

अयोध्या में महापाप हुआ है, एसआईटी का मतलब शेयर इन थेफ्ट मतलब चोरी में हिस्सेदारी – अखिलेश यादव

लखनऊ, (संवाददाता)। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर प्रशासन को सौंपी गई एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी का महापाप हुआ है। विशेष जांच समिति मतलब एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने कहा कि एसआईटी का मतलब शेयर इन थेफ्ट मतलब चोरी में हिस्सेदारी है। उन्होंने मामले में अभी तक एफआईआर न होने को लेकर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव बुधवार को लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने राममंदिर का दर्शन कर दान दिया था। चढ़ावा चढ़ाया था। प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र से अगर 10 करोड़ भी मानें तो 800 करोड़ रुपये का चढ़ावा प्रभु श्रीराम को चढ़ाया गया है। लोग गुप्तदान भी करते हैं। अब गुप्तदान करने वाले अगर बोलेंगे तो उनके घर ईडी और सीबीआई पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश में जमीन घोटाले के लगे आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा कि वहां सत्ता के इंजन आपस में टकरा रहे हैं इसलिए इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं, भाजपा के दूसरे दलों के सांसदों को तोड़ने को लेकर कहा कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है इसलिए सांसदों को जुटा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासी समाज का हक मार रही है। प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर आदिवासी समाज को जल, जंगल और जमीन पर पूरा अधिकार मिलेगा। इसके पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर कहा कि एफआईआर के बिना एसआईटी 'बिना तीर की कमान' है। अब दान में दिये गये 'कागभुसुंडि' के गायब हो जाने की निंदनीय खबर आई है।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, 4 गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 23 जून को घोषणा की कि लखनऊ के अलीगंज इलाके में लगी जानलेवा आग, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी, उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस घटना के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। पाठक ने कहा कि कल रात से अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में सखब्त कार्रवाई की जाएगीय किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस सांसद जेबी माथर ने ऐसी घटनाओं के बार–बार होने पर चिंता जताई और जवाबदेही तय करने और सुरक्षा के बेहतर नियम लागू करने की मांग की। उन्होंने ।छप् से कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं बार–बार होती रहती हैं – हमने इसे दिल्ली में देखा और अब लखनऊ में। ऐसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए क्या सिस्टम है? सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि क्या गड़बड़ हुई और यह पक्का करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए कि ऐसी घटनाएं कहीं भी दोबारा न हों। लखनऊ पुलिस ने अलीगंज पुलिस स्टेशन इलाके की उस बिल्डिंग को सील कर दिया है जहां आग लगी थी। आम लोगों के आने–जाने पर रोक लगा दी गई है क्योंकि फोरेंसिक और फायर डिपार्टमेंट की टीमें सबूत इकट्ठा कर रही हैं। जगह को सुरक्षित रखने और जांच में मदद के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

तनाव और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही दुनिया में ब्रिक्स की है खास भूमिका – अजित डोभाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज मंगलवार को कहा कि ब्रिक्स केवल देशों के समूह से कहीं ज्यादा है। उन्होंने इसे दुनिया की लगभग आधी आबादी का एक सामूहिक घर बताया, जिसकी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में "खास भूमिका" है। खासतौर से ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय सिस्टम बढ़ती अस्थिरता, भू–राजनीतिक तनाव और बदलते सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है। 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सालहकारों की मीटिंग में एनएसए अजित डोभाल ने अपने समकक्षों का स्वागत किया और सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने समूह के अंदर सहयोग को आगे बढ़ाने में लगातार जुड़े रहने और समर्थन के लिए हिस्सा लेने वाले देशों को धन्यवाद दिया। एनएसए अजित डोभाल ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, "मैं आज आपकी मौजूदगी और ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के आपके लगातार कमिटमेंट के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं।" मौजूदा वैश्विक हालात को हाइलाइट करते हुए, उन्होंने कहा कि दुनिया एक खास तौर पर मुश्किल दौर से गुजर रही है, जिसमें हथियारों से जुड़ी लड़ाइयां, भू–राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक दबाव और ऐसी विघटनकारी प्रौद्योगिकी का आना शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के माहौल को बदल रही हैं। उन्होंने कहा, "हम बहुत मुश्किल समय में मिल रहे हैं। दुनिया सैन्य झगड़ों और मुश्किल सुरक्षा समस्याओं से जूझ रही है। यह भू–राजनीतिक अनिश्चितताओं, आर्थिक दबाव और विघटनकारी प्रौद्योगिकी का सामना कर रही है।" एनएसए अजित डोभाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने जो चुनौतियां हैं, वे तेजी से मुश्किल होती जा रही हैं और उन्हें मैनेज करना कठिन हो रहा है, जबकि मौजूदा संस्थागत फ्रेमवर्क और झगड़े सुलझाने के तरीके असरदार तरीके से जवाब देने में मुश्किल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, "न केवल खतरे और अधिक जटिल तथा आपस में जुड़े हुए होते जा रहे हैं, बल्कि उनसे निपटने या उनके प्रभाव को कम करने के लिए मौजूद साधन और संस्थागत तंत्र भी लगातार अपर्याप्त साबित हो रहे हैं।" बहुपक्षीय सहयोग के कमजोर होने पर चिंता जताते हुए, एनएसए डोभाल ने कहा कि ग्लोबल सिस्टम में बहुपक्षवाद में गिरावट देखी जा रही है, ऐसे समय में जब मिलकर काम करने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। उन्होंने ब्रिक्स बनाने के पीछे के असली विजन को याद करते हुए कहा, "बहुपक्षावाद कम हो रहा है।" एनएसए अजित डोभाल के अनुसार, ब्रिक्स को उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के एक अनौपचारिक समूह के तौर पर सोचा गया था, जिसका मकसद ज्यादा "मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर" को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय मामलों में ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना था।

संपादकीय

बढ़ती आर्थिक चुनौतियां

वित्त मंत्रालय के मुताबिक तीन कारणों से दुनिया नया आकार ले रही हैरू महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा, पश्चिमी गठबंधन में दरार, और मैनुफैक्चरिंग में चीन का वर्चत्व। इसके अनुरूप ढलने के लिए भारत के पास बहुत कम वक्त है। बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच वैश्विक आपूर्ति शृंखला में आए बदलावों से तालमेल बनाने के लिए भारत के पास एक बहुत छोटी खिड़की मौजूद है। यह बात केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्थायी संसदीय समिति के सामने कही। बताया गया कि चीन ने अपने नए कानून के तहत वहां स्थित आपूर्ति शृंखला को बाधित कर दिया है। वहां से अपने कारखाने हटाने वाली कंपनियों को वह दंडित कर रहा है। इससे भारत में मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई नीति के सामने मुश्किलें खड़ी हुई हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस समय ये तीन परिघटनाएं दुनिया को नया आकार दे रही हैरू बड़ी ताकतों में प्रतिस्पर्धा, पश्चिमी गठबंधन में दरार, और मैनुफैक्चरिंग में चीन का प्रभुत्व। मंत्रालय ने कहा कि इन परिवर्तनों पर भारत को अधिक फुर्तीला और रणनीतिक प्रतिक्रिया दिखानी होगी। ऐसा करने के लिए देश के पास शबहुत छोटा अवसरस्य है। मंत्रालय ने कहा कि महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के तहत व्यापार, तकनीक, और वित्त का उपयोग सामान्य लाभ उठाने के बजाय रणनीतिक हितों के मुताबिक किया जा रहा है। इसी क्रम में चीन ने अपने यहां से कारखाना, तकनीक, या विशेषज्ञों को दूसरे देशों में– खासकर भारत ले जाने की राह में कानूनी रुकावट खड़ी कर दी है। भारत में साझा उद्यम या देशी निवेश के तहत लगाए जा रहे कारखानों की इन मामलों में चीन पर निर्भरता रही है। स्पष्टतरू ये दोनों परिघटनाएं भारत के लिए चुनौती बनकर आई हैं। हालांकि यूरोप और अमेरिका के बीच पड़ती दरार को वित्त मंत्रालय ने भारत के लिए अवसर के रूप में देखा है, मगर इसका लाभ उठाने के लिए तुरंत खुद को तैयार करने की चुनौती उसके सामने है। मंत्रालय ने माना कि इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं है। कहा जा सकता है कि वित्त मंत्रालय को बदल रही दुनिया का सही अहसास है। मगर, नई परिस्थितियों के मुताबिक नजरिए एवं नीतियों में जिस तरह के आमूल परिवर्तन की जरूरत है, उसकी समझ का संकेत उसने नहीं दिया है। क्या बिना घरेलू बाजार के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किए, नए बाहरी हालात का मुकाबला किया जा सकता है– यह बुनियादी सवाल है।

वेतन से आगे- विकसित भारत के लिए कुशल कार्यबल की तैयारी

डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम

कोयंबटूर में काम करने वाले युवा रवि को, जो एक छोटी विनिर्माण इकाई में अपनी पहली औपचारिक नौकरी के छह महीने पूरे कर चुके हैं और हाल ही में अपनी मासिक तनख्वाह के अलावा उन्हें बैंक खाते में 7,500 रुपये मिले। लगातार छह महीने की नौकरी पूरी होने के बाद यह रकम अपने आप जारी कर दी गई। इससे पहले उनका परिवार सिर्फ अनौपचारिक काम करता था, जिसमें कोई अनुबंध, भविष्य निधि में योगदान या नौकरी का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता था। यह पहला मौका था, जब उनकी नौकरी को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया और उन्हें इस तरह का लाभ मिला। रवि को मिली यह धनराशि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम–वीबीआरवाई) के भाग ए के तहत मिली पहली किस्त है। इस योजना को केंद्रीय बजट 2024–25 में प्रधानमंत्री के रोजगार और कौशल पैकेज के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था। इस प्रावधान के तहत, ईपीएफओ में पंजीकृत कंपनियों में पहली बार नौकरी पाने वाले ऐसे कर्मचारी, जिनकी मासिक कमाई 1 लाख रुपये से कम है, उन्हें 15,000 रुपये तक का नकद प्रोत्साहन मिलता है। यह रकम दो किस्तों में दी जाती हैरू पहली किस्त लगातार छह महीने की नौकरी के बाद और दूसरी किस्त बारह महीने के बाद। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी को ईपीएफओ पोर्टल के जरिए वित्तीय साक्षरता का कोर्स पूरा करना होगा और यह राशि बचत के एक साधन में जमा की जाएगी, ताकि कर्मचारी को एक आर्थिक सुरक्षा मिल सके। रवि के लिए, ये छह महीने सिर्फ योग्यता हासिल करने का समय नहीं थे। ये वो वक्त था, जिसमें उन्होंने अपने काम की जगह को समझा, अपने काम से जुड़ी बुनियादी कौशल और योग्यता सीखी और अपने लिए रोजगार का एक रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, जो पहले कभी नहीं था। यह समय उनके नियोक्ता के लिए भी अहम था, जो एक छोटी विनिर्माण इकाई थी और उसने अपने विस्तार के तहत रवि को काम पर रखा था। पीएम–वीबीआरवाई के भाग क्च में प्रावधान है कि जो नियोक्ता अपनी मौजूदा बेसलाइन से ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं, उन्हें हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपये तक का सरकारी योगदान मिलता है। यह योगदान अलग–अलग क्षेत्रों में दो साल तक और विनिर्माण क्षेत्र में चार साल तक मिलता है। यह योगदान उस शुरुआती लागत का कुछ हिस्सा कवर करता है, जो किसी कंपनी को नए कर्मचारी को रखने पर उठानी पड़ती है, खासकर तब जब ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण चल रहा होता है और बिना किसी पिछले औपचारिक अनुभव वाला कर्मचारी, धीरे–धीरे कंपनी के लिए लाभप्रद हो रहा होता है। इस शुरुआती लागत को कम करके यह प्रावधान, योजना का दायरा रवि जैसे लोगों को काम पर रखने वाले छोटे व्यवसायों तक बढ़ाता है। उसकी जैसी विनिर्माण इकाईयों के लिए, चार साल की अवधि, जो सामान्य अवधि से दोगुनी है, कंपनियों को ऑटोमेशन में निवेश के साथ–साथ अपने कार्यबल का विस्तार करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। भारत की जनसांख्यिकीय व्यवस्था को देखते हुए, युवा और बढ़ता कार्यबल 2047 तक विकसित भारत की ओर बढ़ने के लिए रोजगार–आधारित विकास के जरिए आर्थिक विकास को रफ्तार देने का एक मौका देता है। कार्यबल में शामिल होने वाले नए लोग किस सीमा तक औपचारिक रोजगार में आते हैं, जहाँ उन्हें सामाजिक सुरक्षा और संस्थागत सुरक्षा मिलती है, यह इस बात पर भी असर डालेगा कि परिवारों और समुदायों में विकास का लाभ कैसे मिलता है। पीएम–वीबीआरवाई का मकसद स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत तक के सफर को मजबूत करना है और दो साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा औपचारिक नौकरियाँ पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इस योजना की शुरूआत से, 60 लाख नए कर्मचारी औपचारिक कार्यबल का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें से 43.26 लाख (लगभग 71त्न) 18 से 30 साल की उम्र के हैं और 18.04 लाख (लगभग 30त्न) महिलाएं हैं, जो पहली बार औपचारिक रोजगार से जुड़ी हैं। ये कर्मचारी विशेष सेवाओं, इंजीनियरिंग, व्यापार, विनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो दिखाता है कि कई तरह के औपचारिक संस्थानों में इसे अपनाया गया है। सिर्फ प्रोत्साहन राशि के अलावा, पीएम–वीबीआरवाई से रवि को एक ईपीएफओ खाता और एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिला है। इससे वह एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं, जो भविष्य निधि योगदान, बीमा सुरक्षा और कानूनी रोजगार लाभ भी देता है। उनके जैसे पहली बार औपचारिक रोजगार पाने वाले कई लोगों के लिए, यह सामाजिक सुरक्षा कवरेज और एक व्यवस्थित रोजगार से जुड़ने का एक बेहतर मौका है।

सऊदी ने पाक से बढ़ाए रक्षा संबंध तो जवाब में संयुक्त अरब अमीरात भारत से करेगा बड़ी डील

नीरज

पश्चिम एशिया की बदलती शक्ति राजनीति के बीच भारत के लिए एक जबरदस्त रणनीतिक अवसर उभरता दिखाई दे रहा है। संयुक्त अरब अमीरात अब भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाशतीर वायु रक्षा प्रणाली खरीदने पर गंभीर बातचीत कर रहा है। यह खाड़ी क्षेत्र की बदलती सामरिक दिशा का खुला संकेत है। देखा जाये तो यह वही क्षेत्र है जहां पाकिस्तान दशकों तक इस्लामी सैन्य एकजुटता के नाम पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच चल रही यह बातचीत उस समय सामने आई है जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। दोनों देशों के बीच ऐसे समझौते हुए हैं जिनमें सुरक्षा सहयोग और सैन्य प्रतिक्रिया का पहलू भी शामिल है। ऐसे में सऊदी अरब के पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात का भारत की सबसे घातक और चर्चित मिसाइल प्रणाली में रुचि दिखाना केवल व्यापारिक फैसला नहीं माना जा सकता। इसके पीछे पश्चिम एशिया की गहरी शक्ति प्रतिस्पर्धा और पाकिस्तान को लेकर बदलती सोच साफ दिखाई देती है। हम आपको बता दें कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज परिचालन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों माध्यमों से दागा जा सकता है। भारत और रूस ने मिलकर इसे विकसित किया है। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के बाद यदि संयुक्त अरब अमीरात इसे खरीदता है तो यह भारत के रक्षा निर्यात इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल होगा। इससे भारत केवल हथियार बेचने वाला देश नहीं बल्कि वैश्विक सामरिक संतुलन बनाने वाला शक्ति केंद्र बनकर उभरेगा। आकाशतीर प्रणाली की चर्चा भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह भारत की स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली है, जिसे भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। हाल के संघर्षों में ड्रोन और मिसाइल हमलों ने जिस तरह युद्ध की तस्वीर बदल दी है, उसके बाद खाड़ी देश अपनी वायु सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हो गए हैं। ईरान, इजराइल और क्षेत्रीय संघर्षों के कारण पूरा पश्चिम एशिया अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे माहौल में संयुक्त अरब अमीरात ऐसी रक्षा प्रणाली चाहता है जो तेज, सटीक और बहुस्तरीय सुरक्षा दे सके। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संयुक्त अरब अमीरात अब केवल अमेरिका या पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वह अपने रक्षा आपूर्तिकर्ताओं का दायरा बढ़ा रहा है ताकि किसी एक शक्ति के दबाव में न आना पड़े। भारत उसके लिए आदर्श विकल्प बनकर उभरा है क्योंकि भारत तकनीकी रूप से सक्षम है, तेजी से उभरती सैन्य शक्ति है और पश्चिम के साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं। यहीं पर पाकिस्तान की बेचैनी शुरू होती है। दशकों तक पाकिस्तान खाड़ी देशों के लिए सैन्य सहयोगी बना रहा। पाकिस्तानी सेना ने सऊदी अरब और खाड़ी देशों में प्रशिक्षण से लेकर सुरक्षा तक में भूमिका निभाई। लेकिन अब वही खाड़ी देश भारत की सैन्य तकनीक पर भरोसा दिखा रहे हैं। यह पाकिस्तान की रणनीतिक हार है। देखा जाये तो संयुक्त अरब अमीरात के पाकिस्तान से दूर जाने के पीछे केवल सामरिक कारण नहीं हैं, बल्कि भरोसे का संकट भी है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली, कट्टरपंथी संगठनों को लेकर उसकी खराब छवि, आतंकवाद को लगातार समर्थन और राजनीतिक अस्थिरता ने खाड़ी देशों का विश्वास कमजोर किया है। संयुक्त अरब अमीरात को यह समझ आ गया है कि पाकिस्तान भरोसेमंद साझेदार नहीं रह गया, जबकि भारत एक स्थिर, मजबूत और तेजी से उभरती वैश्विक शक्ति बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच बनी व्यक्तिगत केमिस्ट्री ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। मोदी के कार्यकाल में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि रक्षा, ऊर्जा, निवेश, आतंकवाद विरोधी सहयोग और समुद्री सुरक्षा तक फैल गए। यही वजह है कि आज अबू धाबी को भारत केवल हथियार बेचने वाला देश नहीं, बल्कि ऐसा रणनीतिक साथी नजर आ रहा है जो संकट की घड़ी में मजबूती से साथ खड़ा रह सकता है। इसके अलावा, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के रिश्तों में हाल के वर्षों में तनाव बढ़ा है। तेल उत्पादन, यमन नीति, क्षेत्रीय नेतृत्व और आर्थिक प्रतिस्पर्धा जैसे कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद सामने आए हैं। ऐसे में यदि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ गहरे रक्षा संबंध बना रहा है तो संयुक्त अरब अमीरात का भारत की ओर झुकाव एक संतुलनकारी रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अब

खाड़ी की राजनीति दो अलग ध्रुवों की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान का पारंपरिक सामरिक समीकरण है, तो दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात भारत के साथ नई रणनीतिक धुरी बनाता दिख रहा है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद लाभकारी है क्योंकि इससे उसे पश्चिम एशिया में अभूतपूर्व सामरिक पहुंच मिल सकती है। भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पिछले वर्ष पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान ब्रह्मोस के प्रभावी उपयोग ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इसके बाद कई देशों ने इस मिसाइल में रुचि दिखाई। थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चिली जैसे देश भी इसे खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। यानी भारत अब केवल हथियार आयात करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2026 में समाप्त वित्तीय वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात चार अरब डॉलर के पार पहुंच गया, जबकि 2013–14 में यह केवल 7.26 करोड़ डॉलर था। यह उछाल बताता है कि भारत की रक्षा तकनीक अब विश्व स्तर पर भरोसेमंद मानी जा रही है। बहरहाल, यदि संयुक्त अरब अमीरात के साथ यह समझौता अंतिम रूप लेता है तो इसके कई दूरगामी परिणाम होंगे। एक तो इससे भारत की सामरिक साख अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचेगी। साथ ही पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि खाड़ी में उसका एकाधिकार खत्म हो चुका है।

युद्धविराम से आगे–विश्व अहिंसा की ओर बढ़ेगा

ललित

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हाल ही में हुआ युद्धविराम ऐसे समय में सामने आया है, जब पश्चिम एशिया युद्ध की लपटों में घिरकर वैश्विक स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। कई सप्ताह तक चले संघर्ष ने क्षेत्र को ऐसे ज्वालामुखी में बदल दिया था, जिसकी प्रत्येक विस्फोटक घटना विश्व अर्थव्यवस्था को झकझोर रही थी। तेल बाजारों में भारी उथल–पुथल थी, निवेशकों में घबराहट बढ़ रही थी और वैश्विक मंदी की आशंकाएं गहराने लगी थीं। ऐसे में युद्धविराम ने विश्व को तत्काल राहत तो दी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या यह समझौता स्थायी शांति की नींव बनेगा या केवल अगले युद्ध से पहले का एक अस्थायी विराम सिद्ध होगा? इतिहास साक्षी है कि युद्धविराम और शांति समझौते तभी टिकाऊ सिद्ध होते हैं, जब उनके पीछे केवल सामरिक विवशता नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारस्परिक विश्वास और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता भी हो। अन्यथा वे केवल संघर्षों के बीच का अंतराल बनकर रह जाते हैं। पश्चिम एशिया का इतिहास ऐसे असंख्य समझौतों का गवाह है, जो कागजों पर तो बने, लेकिन जमीन पर टिक नहीं सके। इस युद्ध के परिणामों का विश्लेषण किया जाए तो सबसे बड़ा लाभार्थी ईरान दिखाई देता है। अमेरिका और इजरायल के सैन्य दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय अलगाव के बावजूद तेहरान न केवल अपने राजनीतिक ढांचे को बचाने में सफल रहा, बल्कि उसने अपने विरोधियों को वार्ता की मेज पर आने के लिए भी बाध्य किया। ईरान अब अपने नागरिकों के समक्ष यह दावा कर सकता है कि उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके। ईरानी नेतृत्व इसे प्रतिरोध की जीत के रूप में प्रस्तुत करेगा। दूसरी ओर इस संघर्ष ने अमेरिका की अजेयता की छवि को भी चुनौती दी है। वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के बाद यह एक और अवसर है, जिसने यह स्पष्ट किया कि केवल सैन्य शक्ति राजनीतिक परिणाम सुनिश्चित नहीं कर सकती। वाशिंगटन ने दबाव बनाया, अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः उसे वार्ता और समझौते का रास्ता अपनाना पड़ा। इससे यह संदेश गया है कि इक्कीसवीं सदी की दुनिया अब केवल शक्ति संतुलन से नहीं, बल्कि संवाद, कूटनीति और बहुपक्षीय सहयोग से संचालित होगी। इजरायल के लिए यह स्थिति राजनीतिक रूप से असहज है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को अपने देश के अस्तित्व के लिए खतरा बताते रहे हैं। इजरायल को आशा थी कि युद्ध के माध्यम से ईरान की सामरिक क्षमता को निर्णायक रूप से कमजोर किया जाएगा। किंतु युद्धविराम के बाद ईरान स्वयं को विजेता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इससे इजरायल के भीतर यह बहस और तीव्र हो सकती है कि क्या क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं की तुलना में महाशक्तियों ने अपने सामरिक हितों को अधिक महत्व दिया। भारत के लिए यह समझौता विशेष महत्व रखता है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पश्चिम एशिया पर अत्यधिक निर्भर है। युद्ध की स्थिति में तेल आपूर्ति बाधित होने, समुद्री व्यापार मार्गों पर संकट उत्पन्न होने और कीमतों में वृद्धि की आशंका ने भारत की चिंता बढ़ा दी थी। युद्धविराम से तेल कीमतों पर दबाव कम होगा, महंगाई नियंत्रित रहेगी और खाड़ी देशों में कार्यरत लाखों भारतीयों की सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी घटेंगी। लेकिन भारत का महत्व केवल एक उपभोक्ता राष्ट्र के रूप में नहीं है, वह आज वैश्विक शांति के एक नैतिक प्रवक्ता के रूप में भी उभर रहा है। दरअसल, यह युद्ध एक बड़े प्रश्न को जन्म देता है–क्या मानव सभ्यता युद्धों के सहारे अपने भविष्य का निर्माण कर सकती है? आज महाशक्तियों ने ऐसी विनाशकारी सैन्य क्षमता अर्जित कर ली है कि किसी भी देश की एक छोटी–सी भूल संपूर्ण मानवता को विनाश की ओर धकेल सकती है। परमाणु हथियारों, जैविक अस्त्रों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित युद्ध प्रणालियों के युग में युद्ध अब केवल सीमाओं का प्रश्न नहीं रह गया है, वह समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। यही कारण है कि आज दुनिया को शक्ति की नहीं, शांति की राजनीति की आवश्यकता है। हिंसा, युद्ध, आतंकवाद और शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा ने मानवता को भय, अविश्वास और असुरक्षा के गर्त में धकेल दिया है। यदि विश्व को बचाना है, तो उसे निःशस्त्रीकरण, अहिंसा, सह–अस्तित्व और संवाद की दिशा में आगे बढ़ना ही होगा। इस संदर्भ में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। भारत ने सदैव विश्व को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया है। महात्मा गांधी ने कहा था, 'आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी।' आज यह कथन पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो उठा है। भारत की सांस्कृतिक चेतना 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धांत पर आधारित रही है, जो सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार मानती है। यही कारण है कि भारत ने सदैव युद्ध के स्थान पर संवाद और टकराव के स्थान पर सहमति का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्व के अनेक मंचों पर स्पष्ट रूप से कहा है कि 'यह युग युद्ध का नहीं है।' संयुक्त राष्ट्र, जी–20, ब्रिक्स तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने बार–बार इस बात पर बल दिया है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं, बल्कि वार्ता है। यदि अंततः देशों को बातचीत की मेज पर ही लौटना पड़ता है, तो युद्ध की भयावह कीमत चुकाने की आवश्यकता ही क्या है? भारत की विदेश नीति आज एक नए स्वरूप में सामने आ रही है। रूस–यूक्रेन युद्ध हो, इजरायल–फिलिस्तीन संघर्ष हो अथवा पश्चिम एशिया का वर्तमान संकट–भारत ने किसी पक्ष विशेष का अंध समर्थन करने के बजाय संतुलन, संवाद और शांतिपूर्ण समाधान की नीति अपनाई है। यही संतुलित दृष्टिकोण भविष्य में भारत को वैश्विक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की दिशा में अग्रसर कर सकता है। लेकिन केवल सरकारें ही शांति स्थापित नहीं कर सकतीं। शांति का आधार समाजों, संस्कृतियों और मनुष्यों के भीतर निर्मित होता है। जब तक राष्ट्रवाद आक्रामकता का रूप लेता रहेगा, जब तक हथियार उद्योग युद्धों को लाभ का साधन बनाकर चलता रहेगा और जब तक राजनीतिक नेतृत्व युद्ध को लोकप्रियता अर्जित करने के उपकरण के रूप में उपयोग करता रहेगा, तब तक स्थायी शांति का सपना अधूरा रहेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व समुदाय कुछ ठोस कदम उठाए–परमाणु एवं सामरिक हथियारों की होड़ को नियंत्रित किया जाए, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाया जाए, अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए स्थायी संवाद तंत्र विकसित किए जाएं और शिक्षा प्रणालियों में शांति एवं अहिंसा के मूल्यों को शामिल किया जाए। साथ ही युद्ध अर्थव्यवस्था के स्थान पर मानव कल्याण आधारित विकास मॉडल को प्राथमिकता दी जाए। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हुआ युद्धविराम निश्चय ही राहत का क्षण है, किंतु इसे स्थायी शांति में परिवर्तित करना अभी शेष है।

सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र– 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत का दृष्टिकोण

2014 और 2026 के बीच, सरकार ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं पर केंद्रित कई पहल शुरू कीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के विजन के आधार पर, सरकार ने शिक्षा तक पहुँच बढ़ाई, उच्च शिक्षा को मजबूत किया और कौशल विकास व रोजगार के अवसर बढ़ाए। भारत के स्टार्टअप तंत्र में भी इजाफा हुआ, जिसमें 2.3 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप शामिल हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, समावेशी कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, देश के युवा अमृत पीढ़ी के रूप में उभरे हैं और विकसित भारत ञ्च 2047 के विजन में योगदान दे रहे हैं। अमृत पीढ़ी का उदय अपनी लगभग 65 प्रतिशत आबादी के 35 वर्ष से कम उम्र के होने के कारण, भारत अपने इतिहास के एक अहम मोड़ पर है। सरकार इस जनसांख्यिकीय लाभांश की अपार क्षमता को पहचानती है। पिछले 12 वर्षों में, देश ने युवाओं के साथ सरकार के जुड़ाव के तरीके में एक बुनियादी बदलाव देखा है। यह दौर भारत के युवाओं को राष्ट्रीय विकास की ताकत में बदलने के लिए किए गए व्यवस्थित और परिवर्तनकारी प्रयासों को दर्शाता है। यह बदलाव शिक्षा, कौशल विकास, खेल और उद्यमिता सहित हर क्षेत्र में दिखाई देता है। युवाओं को अब केवल निष्क्रिय लाभार्थी नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें अमृत पीढ़ी के रूप में पहचाना जाता है। वे विकसित भारत ञ्च 2047 के मुख्य निर्माता और सह–रचनाकार के रूप में उभरे हैं। युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान पिछले दशक में युवाओं के विकास के प्रति भारत के नजरिए में काफी बदलाव आया है, जो युवा और गतिशील आबादी की बदलती आकांक्षाओं और जरूरतों को दर्शाता है। राष्ट्रीय युवा नीति (एनवाईपी) 2014 ने देश में युवाओं के विकास के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया। इसमें 15–29 साल के लोगों को युवा माना गया और शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य, खेल, सामाजिक भागीदारी और सशक्तिकरण जैसे अहम क्षेत्रों की पहचान की गई। इसका मुख्य जोर पहुँच, समावेश और संस्थागत मजबूती पर था। इसी बुनियाद को आगे बढ़ाते हुए, सरकार ने हाल के वर्षों में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास का विजन पेश किया है। इसमें युवाओं को सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों का लाभार्थी के तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्र–निर्माण में सक्रिय साझेदार के तौर पर देखा गया है। हाल ही में प्रस्तावित राष्ट्रीय युवा नीति 2025 का ढांचा भविष्य के लिए जरूरी कौशल, उद्यमिता, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी, डिजिटल भागीदारी और टिकाऊ विकास जैसी उभरती प्राथमिकताओं पर और जोर देता है। हाल के वर्षों में शिक्षा के प्रति भारत का नजरिया काफी बदला है। अब ध्यान सिर्फ पहुँच बढ़ाने से हटकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो गया है। शिक्षा अब शहरों तक ही सीमित न रहकर दूर–दराज के इलाकों तक पहुँच रही है, ताकि सभी को समान अवसर मिल सकें। भारत के युवाओं के लिए सर्वांगीण और भविष्य के लिए तैयार करने वाली शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) इस बदलाव का मुख्य आधार है। यह देश भर के हितधारकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श के बाद तैयार की गई पहली व्यापक शिक्षा नीति है। यह नीति सीखने वाले को व्यवस्था के केंद्र में रखती है और अनुभव–आधारित तथा बहु–विषयक शिक्षा को बढ़ावा देती है। एनईपी अमृत पीढ़ी को सशक्त बनाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। पिछले दशक में, सरकार ने युवा सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा की नींव के तौर पर स्कूली शिक्षा को मजबूत किया है। एनईपी 2020 के अनुरूप, स्कूली शिक्षा को प्री–प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक एक एकीकृत और निरंतर प्रक्रिया के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है। वर्ष 2025–26 तक, 1.49 लाख से ज्यादा स्कूलों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और डिजिटल पहलों के दायरे में लाया गया है, साथ ही, 1.76 लाख से अधिक स्मार्ट क्लासरूम और 1.79 लाख आईसीटी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है। अलग–अलग सामाजिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं को शामिल करने और उन्हें पढ़ाई से जोड़े रखने पर खास जोर दिया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों (एनएससीबीएवी) जैसी आवासीय स्कूली सुविधाओं ने लड़कियों और सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों वाले छात्रों, खासकर दूर–दराज और चुनौतीपूर्ण इलाकों में रहने वालों के लिए शिक्षा तक पहुँच को बेहतर बनाया है। इन कोशिशों के साथ–साथ, पीएम–जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) जैसी पहलों के तहत हॉस्टल सुविधाओं ने आदिवासी समुदायों के लिए शिक्षा के मौकों को बढ़ाया है। इन उपायों से सभी स्कूली स्तरों पर दाखिले में सुधार हुआ है और स्कूल छोड़ने वालों की दर में कमी आई है, जिससे ज्यादा भारतीय युवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी कर पा रहे हैं। नई शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा तक पहुँचने और उसे देने के तरीके में बुनियादी बदलाव किए हैं। भारतीय युवा अब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के जरिए सशक्त हो रहे हैं, जो ज्यादा सशक्त, डिजिटल रूप से सक्षम और नवाचार पर आधारित है। एनईपी 2020 ने ऐसे संरचनात्मक सुधार किए हैं, जो युवाओं को उनकी शैक्षणिक यात्रा पर ज्यादा नियंत्रण प्रदान करते हैं। ' नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), जिसे 170 विश्वविद्यालयों ने अपनाया है, छात्रों को अकादमिक, कौशल आधारित और अनुभव–आधारित शिक्षा के जरिए क्रेडिट जमा करने की सुविधा देता है। ' एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) ने 2,469 संस्थानों को अपने साथ जोड़ा है और 32 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट आईडी जारी किए हैं। यह छात्रों को अपनी अकादमिक प्रगति खोए बिना अलग–अलग संस्थानों में क्रेडिट जमा करने, ट्रांसफर करने और रिडीम करने की सुविधा देता है। ' ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार आईडी) छात्र की सीखने की यात्रा के दौरान हासिल किए गए अकादमिक और कौशल क्रेडिट को इकट्ठा करती है। 31 मार्च, 2026 तक, छात्रों के लिए 15.48 करोड़ से ज्यादा वेरिफाइड अपार आईडी बनाए जा चुके हैं। ' अब 153 विश्वविद्यालय साल में दो बार एडमिशन और कई एंट्री/एक्जिट पॉइंट की सुविधा देती हैं। यह सुविधा 2035 तक उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो (जीईआर) का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए, सरकार ने एक मजबूत डिजिटल लर्निंग व्यवस्था बनाई है। जून 2026 तक, स्वयं ने 18,580 से ज्यादा पाठ्यक्रम प्रदान किए हैं, जिसमें 6.1 करोड़ से ज्यादा नामांकन और 53.7 लाख प्रमाणीकरण दर्ज किए गए हैं। स्वयंप्रभा, पीएम ई–विद्या और दीक्षा टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल कंटेंट और ई–संसाधनों के जरिए सीखने के अवसरों को और बढ़ाया है। अकेले दीक्षा में 135 भाषाओं में 3.66 लाख से ज्यादा ई–कंटेंट संसाधन मौजूद हैं। उच्च शिक्षा के स्तर पर, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल ने 7,414 संस्थानों में अकादमिक और शोध संसाधनों तक पहुंच बढ़ाई है, जिससे लगभग 99 लाख लोगों को फायदा हुआ है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, अटल इनोवेशन मिशन ने 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब बनाई हैं, जिनसे 1.1 करोड़ से ज्यादा छात्रों को मदद मिली है और उभरती तकनीकों में 16 लाख से ज्यादा परियोजनाओं के विकास में मदद मिली है।

कोचिंग सेंटर अग्निकांड-दोषियों पर सख्त कार्रवाई और उच्चस्तरीय जांच की मांग

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित एक कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड में कई मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत पर आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद ँदरंल ँपदही ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस त्रासदी को अत्यंत दुखद बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की। प्रेस को जारी बयान में संजय सिंह ने कहा कि लखनऊ से आई यह खबर बेहद विचलित करने वाली है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य और बड़े सपनों के साथ पढ़ने के लिए भेजा था, आज उन परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने दिवंगत बच्चों की आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में आम आदमी पार्टी पूरी तरह पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।संजय सिंह ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस भवन में कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा था, वहां अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया और उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) किस आधार पर जारी किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी इस प्रकार की लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती।उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। साथ ही जिन अधिकारियों, कर्मचारियों या संस्थान संचालकों की भूमिका लापरवाही में सामने आए, उनके विरुद्ध तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए।राज्यसभा सांसद ने सरकार से मृतक बच्चों के परिजनों को तत्काल पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा घायलों के समुचित और उच्चस्तरीय उपचार की व्यवस्था सरकारी खर्च पर सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को केवल संवेदना नहीं बल्कि ठोस सहायता और न्याय की आवश्यकता है।संजय सिंह ने यह भी मांग की कि इस हादसे से सबक लेते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों, शैक्षणिक परिसरों और व्यावसायिक भवनों का व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट तत्काल शुरू किया जाए।

लखनऊ बाराबंकी रेलखंड का जीएम ने लिया जायजा, स्टेशन निर्माण में तेजी लाने को कहा

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडे ने सोमवार को चारबाग स्टेशन, लखनऊ–बाराबंकी रेलखंड, मल्हौर और बाराबंकी रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्री सुविधाओं को सुदृढ़ करने और चल रहे विकास कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। महाप्रबंधक ने चारबाग स्टेशन पहुंचकर रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा किए जा रहे स्टेशन पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा। इसके बाद उन्होंने लखनऊ–बाराबंकी रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण कर रेल ट्रैक की सुरक्षा और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के अगले चरण में महाप्रबंधक मल्हौर और बाराबंकी स्टेशन पहुंचे। वहाँ उन्होंने श्श्अमृत भारत स्टेशन योजनाश्श के तहत चल रहे विकास कार्यों और यात्री सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने रेलवे की प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं देना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरीक्षण कार्यक्रम के समापन के बाद महाप्रबंधक ने डीआरएम कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर डीआरएम सुनील कुमार वर्मा, सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता और सीनियर डीओएम रजनीश श्रीवास्तव सहित मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जौनपुर में दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड पर धरना जारी ,सपा नेता बोले- जाति देखकर एनकाउंटर, आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। कलेक्ट्रेट परिसर में दूल्हा आजाद बिंद की हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर सौम्या बिंद का धरना सातवें दिन भी जारी रहा। बुधवार को समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लौटन राम निषाद ने धरने का समर्थन किया। पत्रकारों से बात करते हुए निषाद ने आरोप लगाया कि आजाद बिंद को भोले राजभर ने गाड़ी ओवरटेक कर गोली मारी थी। उन्होंने बताया कि भोले राजभर, प्रदीप बिंद और रवि यादव सहित अन्य आरोपियों को एक बड़े नेता के घर से उठाया गया था। बाद में भोले राजभर और प्रदीप बिंद को छोड़ दिया गया, जबकि रवि यादव का एनकाउंटर कर दिया गया। निषाद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर तथा बुलडोजर की कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि अपराधी ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग से है, तो उसे कमर के ऊपर गोली मारी जाती है, जबकि उच्च जाति के अपराधियों को कमर के नीचे गोली मारकर श्हाफ एनकाउंटरश कर लंगड़ा बना दिया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के श्अपराधियों को मिट्टी में मिला देनेश के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आए दिन हो रही घटनाएं कौन से अपराधी कर रहे हैं। निषाद ने यह भी दावा किया कि मृतक की बहन सौम्या बिंद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने डीजीपी से बात की और कार्रवाई का आश्वासन मिला। इसके चार घंटे बाद ही रवि यादव का एनकाउंटर कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भोले राजभर और प्रदीप बिंद को उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोगी दलों, संजय निषाद और ओमप्रकाश राजभर का संरक्षण प्राप्त है। निषाद के अनुसार, उन्हें लखनऊ में जानकारी मिली कि भोले राजभर और शोले राजभर तीन दिनों तक ओमप्रकाश राजभर के सरकारी आवास पर रुके थे, जबकि प्रदीप बिंद संजय निषाद के आवास पर था। जब यह मामला तूल पकड़ने लगा, तो उन्हें कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया।

धरना-प्रदर्शन कर किसानों का समस्याएं दूर करने की मांग, सौंपा ज्ञापन

लखनऊ, (संवाददाता)। किसानों के अंश निर्धारण और फार्मर रजिस्ट्री समेत किसानों की अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय व ब्लॉक मोहलनलालगंज में धरना–प्रदर्शन किया। संगठन के जिलाध्यक्ष राजेश रावत की अगुवाई में कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अंश निर्धारण के सभी लंबित प्रकरणों का समय से निस्तारण करने, फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी बनाने, डीएपी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, नकली कीटनाशक और नकली बीज की बिक्री पर रोक लगाने समेत 15 सूत्री मांग को लेकर उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज पवन पटेल को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर महासचिव राकेश गौतम, विष्णुपाल सिंह, मेवालाल, बीजक प्रकाश, सुजीत, राममिलन आदि मौजूद रहे। इसी तरह मोहनलालगंज में भाकियू कार्यकर्ताओं ने सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कहा कि पेट्रोल पंप पर गैलन में डीजल देने से मना किया जाता है। इस पर उप जिलाधिकारी ने आगे से ऐसा न होने का आश्वासन दिया। अन्य समस्याओं के समाधान के लिए शनिवार को बैठक आयोजित करने की बात कही गई। इस आश्वासन के बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया।

रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर सपा ने दी श्रद्धांजलि

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। नगर के समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर बुधवार की दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रानी दुर्गावती ने 24 जून 1564 को अपने स्वाभिमान और राज्य की रक्षा के लिए वीरगति प्राप्त की थी। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहा कि रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की महान वीरांगनाओं में से एक थीं। उन्होंने अन्याय और आक्रमण के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उनका जीवन संघर्ष, साहस और

आत्मसम्मान की प्रेरणा देता है। गोष्ठी को पूर्व विधायक लालबहादुर यादव, पूर्व विधायक श्रद्धा यादव, जिला उपाध्यक्ष श्यामबहादुर पाल, हीरालाल विश्वकर्मा, महेंद्र प्रताप यादव नेपाल, जिला सचिव अजय त्रिपाठी, गोंड महासभा के जिला उपाध्यक्ष उदयराज गोंड, श्यामनारायण बिंद, हरिश्चंद प्रभाकर और दिलीप प्रजापति सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। विचार गोष्ठी का संचालन करते हुए जिला महासचिव आरिफ हबीब ने कहा कि रानी दुर्गावती का बलिदान देश की महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने सभी से उनके आदर्शों को आत्मसात कर समाज में समानता, न्याय और सम्मान की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सदर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष वीरेंद्र, राजपति गोंड, प्रदीप गोंड, प्रमोद गोंड, मोहन गोंड, पूनम यादव, प्रदीप पाल, रवि यादव, सुनील वासुदेव यादव, गोविंद यादव, कमलेश बिंद और सद्दाम सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की तैयारी

लखनऊ, (संवाददाता)। डिजिटल युग में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों की चुनौतियों से निपटने और पुलिसकर्मियों को आधुनिक तकनीकों से लैस करने के उद्देश्य से लखनऊ पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता विषय पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के क्रम में पुलिस आयुक्त लखनऊ अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में आयोजित यह कार्यशाला रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित संगोष्ठी सदन में सम्पन्न हुई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल की साइबर अपराधों की जांच, रोकथाम और त्वरित कार्रवाई की क्षमता को और अधिक सशक्त बनाना था।कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार, अमित कुमावत तथा अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) किरन यादव के मार्गदर्शन में किया गया।

संक्षिप्त खबरें

2026–27 तक हर बच्चा निपुण' लक्ष्य को गति, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश में '2026–27 तक कक्षा–3 का हर बच्चा निपुण' बनाने के लक्ष्य को साकार करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और गति दे दी है। इसी क्रम में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (एफएलएन) आधारित पांच दिवसीय राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण का दूसरा चरण सोमवार को इंदिरानगर स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सभागार में शुरू हुआ।प्रशिक्षण के पहले दिन अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए राज्य संदर्भ समूह (एसआरजी) सदस्यों और डायट मेंटरों से संवाद करते हुए कहा कि निपुण भारत मिशन प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर्स इस मिशन की सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और कक्षा–कक्ष में होने वाले सकारात्मक बदलाव की नींव इसी प्रशिक्षण से तैयार होगी। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण को केवल औपचारिकता न मानते हुए मिशन मोड में कार्य करने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान और अनुभव को विद्यालय स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना होगा, जिससे बच्चों की आधारभूत भाषा और गणितीय दक्षताओं में अपेक्षित सुधार लाया जा सके। प्रशिक्षण की सफलता तभी मानी जाएगी जब उसका प्रभाव सीधे विद्यार्थियों के सीखने के स्तर पर दिखाई दे।यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यव्यापी शिक्षक क्षमता संवर्धन अभियान की दूसरी कड़ी है। इससे पूर्व पहला चरण 16 से 20 मई के बीच सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। वर्तमान चरण में प्रदेश के 20 जनपदों से प्रत्येक जनपद के दो एसआरजी सदस्य और दो डायट मेंटर भाग ले रहे हैं।

प्रदेश में कृषि आधारित उद्यमों की नई क्रांति, बागपत के किसान – पेंद्र धनकड़ बने मिसाल

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश अपनी उपजाऊ भूमि, प्रचुर जल संसाधनों और विविध कृषि उत्पादन क्षमता के बल पर कृषि आधारित उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, आम और मक्का जैसी फसलों के प्रचुर उत्पादन ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, बीज प्रसंस्करण, जैविक खाद निर्माण तथा पैकेजिंग उद्योगों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। प्रदेश सरकार की नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं के कारण कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।प्रदेश सरकार की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत उद्यमियों को पूंजीगत अनुदान, बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में रियायत तथा ब्याज अनुदान जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। खाद्य प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं पर 35 से 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को प्रति सदस्य 40 हजार रुपये तक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराकर महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है।प्रदेश में गन्ना आधारित उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

एसआईटी ने तीन दिन बाद भी नहीं सौंपी रिपोर्ट, बड़े पदाधिकारी को बचाने की कोशिश की आशंका

लखनऊ, (संवाददाता)। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी को बचाने की जद्दोजहद चल रही है, ताकि वह बेदाग रह सकें। इसलिए मंथन चल रहा है कि किस पर और किस तरह की कार्रवाई की जाए। एसआईटी को लौटे तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंच सकी है। चोरी का मामला उजागर होने के बाद से ट्रस्ट के पदाधिकारी उसे दबाने में जुटे थे। एसआईटी की टीम ने छह दिन तक अयोध्या में तफ्तीश कर चढ़ावे में हेरफेर के साक्ष्य जुटाए। छानबीन में यह भी सामने आया कि पदाधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर किस तरह रिश्तेदारों व करीबियों को मंदिर प्रबंधन में काम पर रखा हुआ था। इसलिए एसआईटी ने एक तरफ आपराधिक कृत्य करने वालों की सूची तैयार की और दूसरी तरफ लापरवाही बरतने वाले बैंक अधिकारियों व ट्रस्ट के पदाधिकारियों के नाम भी रिपोर्ट में शामिल किए। इसमें एक बड़ा नाम भी शामिल है, जिनकी ट्रस्ट में भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। सोशल मीडिया पर उनको लेकर तमाम चर्चाएं भी हैं। सूत्रों के मुताबिक, कार्रवाई में देरी की वजह भी इसी नाम को माना जा रहा है। जब तक इस बारे में ऊपर यानी दिल्ली से निर्देश नहीं मिलेंगे, तब तक कोई कार्रवाई संभव नहीं है। मामले में निर्माण समिति के गोपाल राव चर्चा में हैं। उनकी भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि शनिवार देर शाम एसआईटी के लौटने के बाद गोपाल राव कर्नाटक चले गए और वहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके फोटो और वीडियो भी वायरल हैं। पहले बताया जा रहा था कि एसआईटी ने मंदिर प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों के जिले के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के आरोपों वाले मामले में सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में समयाभाव की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में दाखिल जनहित याचिका (पीआईएल) पर 24 जून को सुनवाई संभावित है। याचिका में मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने और चढ़ावे का ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से कराने की मांग की गई है सोमवार को न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की ग्रीष्म अवकाश कालीन खंडपीठ के समक्ष पीआईएल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। समय की कमी के कारण अदालत इस पर सुनवाई नहीं कर सकी और अब 24 जून को सुनवाई हो सकती है। अधिवक्ता मोहित अशोक द्वारा दाखिल याचिका में अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे में आने वाले धन के कथित गबन की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही कैग से पूरे मामले का ऑडिट कराए जाने की भी अनुरोध किया गया है।

गोरखपुर जंक्शन पर साकार हुआ आध्यात्म और आधुनिकता का संगम

लखनऊ, (संवाददाता)। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने गोरखपुर जंक्शन स्टेशन को यात्रियों के लिए अधिक आकर्षक, ज्ञानवर्धक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक नई पहल की है। महाप्रबंधक उदय बोरवणकर एवं अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ल के मार्गदर्शन में स्टेशन परिसर में यात्री सुविधाओं और सौंदर्यीकरण का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या–2 पर थर्ड एसी प्रतीक्षालय के निकट ध्यान मुद्रा में महात्मा बुद्ध की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा के ऊपर उच्च गुणवत्ता वाली एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिस पर चौबीसों घंटे गोरखपुर जंक्शन के गौरवशाली इतिहास, उसके विकास की यात्रा तथा गोरखपुर और आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी प्रदर्शित की जा रही है। इसके साथ ही बुद्ध प्रतिमा और एलईडी स्क्रीन के मध्य रंग–बिरंगी रोशनी से सुसज्जित 'मेरा प्यारा गोरखपुर' बोर्ड भी लगाया गया है, जो विशेषकर रात्रि के समय यात्रियों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है।रेलवे की इस अभिनव पहल ने स्टेशन को केवल यात्रा का केंद्र ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन जानकारी के मंच के रूप में भी विकसित किया है। आध्यात्मिक शांति, आधुनिक डिजिटल तकनीक और स्थानीय गौरव का यह समन्वय यात्रियों के प्रतीक्षा समय को उपयोगी और यादगार बना रहा है। देश–विदेश से आने वाले पर्यटक यहां तस्वीरें और सेल्फी लेकर गोरखपुर की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर साझा कर रहे हैं।मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बताया कि गोरखपुर बौद्ध सर्किट का प्रमुख प्रवेश द्वार है और स्टेशन पर विकसित की गई यह व्यवस्था 'अतुल्य भारत' तथा 'स्वच्छ व सुंदर स्टेशन' अभियान को नई गति प्रदान कर रही है।

डेंगू की भविष्यवाणी में बीबीएयू के वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता

लखनऊ, (संवाददाता)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के वैज्ञानिकों ने डेंगू जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी की निगरानी और पूर्वानुमान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के डॉ. युसुफ अख्तर और सांख्यिकी विभाग के डॉ. सुभाष कुमार यादव द्वारा किए गए एक व्यापक शोध अध्ययन को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्प्रिंगर नेचर की पत्रिका 'डिस्कवर पब्लिक हेल्थ' में प्रकाशित किया गया है। यह अध्ययन भारत के विभिन्न राज्यों में डेंगू संक्रमण और उससे होने वाली मृत्यु दर के पूर्वानुमान के लिए विकसित मॉडलों का राज्यवार तुलनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने शोध दल को बधाई देते हुए कहा कि यह शोध न केवल विश्वविद्यालय बल्कि देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान खोजने की दिशा में यह अध्ययन एक महत्वपूर्ण कदम है।शोधकर्ताओं ने वर्ष 2017 से 2024 तक भारत के विभिन्न राज्यों में डेंगू के मामलों और मृत्यु दर से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पांच प्रमुख पूर्वानुमान तकनीकोंकृनैव विधि, सरल घातांकीय स्मूदिंग (एसईएस), ऑटो–रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (एआरआईएमए), रैखिक प्रतिगमन तथा सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशनकृका उपयोग किया गया। इन सभी मॉडलों का मूल्यांकन रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर (आरएमएसई) के आधार पर किया गया।अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि शोधकर्ताओं ने पूरे देश के लिए एक ही मॉडल लागू करने के बजाय प्रत्येक राज्य के लिए अलग–अलग सर्वश्रेष्ठ मॉडल का चयन किया। शोध दल का मानना है कि भारत जैसे विशाल और भौगोलिक, सामाजिक तथा जलवायु विविधताओं वाले देश में संक्रामक रोगों के पूर्वानुमान के लिए एक समान मॉडल प्रभावी नहीं हो सकता। यही कारण है कि राज्यवार विश्लेषण इस शोध की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि माना जा रहा है।शोध के निष्कर्षों के अनुसार वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में डेंगू के मामलों तथा मौतों में वृद्धि की संभावना है। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि इन राज्यों में स्वास्थ्य विभागों को समय रहते अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था, अस्पतालों की तैयारी और मच्छर नियंत्रण कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों से परेशान थे पड़ोसी

लखनऊ, (संवाददाता)। अलीगंज सेक्टर–डी में सोमवार दोपहर जिस बहुमंजिला भवन में आग लगी, वह आवासीय इलाके में बनाई गई है। इसकी व्यावसायिक गतिविधियों के चलते पड़ोसी परेशान थे। वाहनों की पार्किंग, भीड़भाड़ व आए दिन होने वाली किचकिच को लेकर पड़ोसियों ने कई बार शिकायतें भी कीं। आंचलिक विज्ञान नगरी से आगे बढ़ने पर दाहिनी ओर जो सड़क है, वहां आगे रिहायशी इलाका है। जिस बिल्डिंग में आग लगी, उस तरफ 15 मकान हैं। इन मकानों में एक गली से अगली गली के बीच स्थित इन मकानों में सिर्फ दो व्यावसायिक प्रतिष्ठान ही हैं, जिसमें से एक में सोमवार को आग लग गई। पड़ोस में रहने वाली महिला ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि व्यावसायिक गतिविधियों के चलते पड़ोसियों का चैन से रहना मुहाल हो गया था। पार्किंग को लेकर किचकिच होती थी। इतना ही नहीं लोगों की आवाजाही के चलते भी कहासुनी की नौबतें आती रही हैं। अलीगंज में जहां हादसा हुआ है, उसके सामने गहरा नाला है। इस नाले पर कई जगहों पर पत्थर नहीं हैं। इससे लोगों के नाले में गिरने की आशंका बनी हुई है। लिहाजा सोमवार को जब दुर्घटना हुई तो रात के अंधेरे में नाले में लोग गिर न जाएं, इसके लिए सुरक्षाकर्मियों को तैनात करना पड़ा। अलीगंज में आग की घटना की सूचना मिलते ही यूट्यूबर और इंफ्लुएंसरों का भी जमावड़ा हो गया, जिसे हटाने में सुरक्षाकर्मियों को देर रात तक मशक्कत करनी पड़ी। रीलबाजों को कई बार मौके से खदेड़ा गया। बहुमंजिला भवन के निचले तल पर जानवरों के खानपान पेट फूड की दुकान थी। यह भी आग में जलकर खाक हो गई। इसके बाद मौके पर बचे डॉग फूड के पैकेटों को भी लोग उठा ले गए।

'रेड क्रॉस की पहल पर सहयोग संस्था ने निभाई मानवता की मिसाल, अग्निपीड़ित परिवार को प्रदान की सहायता सामग्री'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' जनपद में मानव सेवा एवं पीड़ित सहायता के क्षेत्र में कार्यरत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के आग्रह पर सहयोग संस्था ने एक जरूरतमंद अग्निपीड़ित परिवार की सहायता कर मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। ज्ञातव्य है कि विकलांग जन कल्याण समिति महिला मोर्चा की अध्यक्ष मीनू मिश्रा के आवास पर आग लग जाने से घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया था, जिससे परिवार को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपने स्तर से यथासंभव सहयोग प्रदान किया तथा अतिरिक्त सहायता हेतु सहयोग संस्था के संस्थापक एडवोकेट शहनवाज खान से अनुरोध किया। रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर रेडक्रॉस कार्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एडवोकेट शहनवाज खान से अग्निपीड़ित परिवार की सहायता का अनुरोध किया गया। उन्होंने तत्काल सहयोग का आश्वासन दिया। इसी क्रम में बुधवार को सहयोग संस्था के पदाधिकारियों ने अपने निजी कार्यालय कच्चा कटरा स्थित मिलन मैरिज लॉन में मीनू मिश्रा को एक बक्सा एवं सीलिंग फैन, वाटर कूलर, विस्तर, कुछ जोड़ी कपड़े, छाता आदि भेंट कर सहायता प्रदान की गई। इस अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉ विजय जौहरी ने कहा कि जिस संस्था का नाम ही "सहयोग" है, वह वास्तव में अपने नाम के अनुरूप समाज के पीड़ित एवं जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि सभी सामाजिक संस्थाओं को सहयोग संस्था से प्रेरणा लेते हुए एक–दूसरे के दुःख–दर्द में सहभागी बनना चाहिए। पीड़ित मानवता की सेवा ही सच्ची सामाजिक सेवा है।

डॉ जौहरी ने इस मानवीय सहयोग के लिए सहयोग संस्था, उसके संस्थापक एडवोकेट शहनवाज खान एवं समस्त पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सहयोग संस्था के संस्थापक मोहम्मद शाहनवाज खान (एडवोकेट)अनिल कुमार गुप्ता (प्रधान) जिला प्रभारी विकास सक्सेना ,अध्यक्ष स्तुति गुप्ता महासचिव हरजीत सिंह , ,उपाध्यक्ष शिवम वर्मा (एडवोकेट), डायरेक्टर,सोमेश यादव, जितेंद्र सिंह ,सैय्यद अनवर शालू यादव रजनी गुप्ता, सचिव सुमन गुप्ता दिव्यांगजन कल्याण समिति के बालकृष्ण पाण्डेय, मीनू मिश्रा,बृजेश गुप्ता, राखी बनकोटी अनुज जोहरी, अग्रज जौहरी अवनीश सक्सेना आदि मौजूद रहे। अंत में रेडक्रॉस सचिव ने सभी का आभार प्रकट करते हुए मानव सेवा में सभी से सहयोगी भूमिका की अपेक्षा की।

राम मंदिर मे दान,चढ़ावा प्रकरण की निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। जिला कांग्रेस कमेटी अयोध्या एवं महानगर कांग्रेस कमेटी अयोध्या के संयुक्त तत्वावधान में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अयोध्या के माध्यम से सौंपा गया।ज्ञापन में अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामधनध्दानध्यढ़ावा से संबंधित कथित घोटालेध अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, एफ. आई.आर. दर्ज करने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई।इस अवसर पर जिलाध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि श्रीराम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यदि मंदिर के धन के दुरुपयोग अथवा अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती हैं तो उनकी निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच होना आवश्यक है।उन्होंने कहा कि जनता की आस्था से जुड़े इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए।महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि सरकार को इस पूरे प्रकरण में तत्काल एफ. आई.आर. दर्ज कराकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच की प्रक्रिया और निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं से जुड़े मामलों में पूर्ण पारदर्शिता लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की।पीसीसी सदस्य राम और पासी तथा पूर्व जिलाध्यक्ष रामदास वर्मा ने कहा कि पार्टी जनभावनाओं एवं श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी तथा इस मामले में न्याय मिलने तक अपनी आवाज बुलंद रखेगी।इस अवसर पर प्रमुख रूप से पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा ,राम अवध पासी, हरजीत सिंह सलूजा, व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह,अशोक कनौजिया, बृजेशरावत, पूर्व पार्षद जनार्दन मिश्रा ,प्रवीण कुमार श्रीवास्तव,उमेश उपाध्याय , पंकज सिंह,धीरेंद्र सिंह बबलू, अनिल शर्मा नीलम, कवींद्र साहनी, राजकुमार पांडे ,भीम शुक्ला ,वाजिद अली, मोहम्मद आमिर, आदि उपस्थित रहे।

पीड़ित ने पुलिस पर लगाया विपक्षी से मिलीभगत कर कार्यवाही करने का आरोप

अयोध्या। थाना महाराजगंज क्षेत्र के गांव अमारी निवासी मेवालाल ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया की मामूली विवाद के चलते उसके परिजनों को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा।जिसके चलते उसके पुत्र सहित अन्य परिजनों को गंभीर चोटें आई।आरोप लगाया कि उल्टे ही पुलिस ने इस पर कार्यवाही भी किया।बताया कि शनिवार को जब उसका पुत्र शिवनाथ अपने घर के पास था तभी किसी बात को लेकर विपक्षी जिसमें शिवराज,धीरज, रिंकी,पिंकी,कालिका, दिलीप,अनुज, सुरजीत सहित अन्य लोगों ने लाठी डेंडर से उसके तथा उनके परिजनों पर हमला कर दिया जिसमें उनके परिजनों को गंभीर चोटें आई बताया कि जब वह इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दिया तो इससे पहले ही उसने स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाया की पुलिस ने विपक्षी की तहरीर लेकर उल्टे ही उसे शांतिभंग मे कार्यवाही किया। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक थाना महाराजगंज ने बताया कि इस मामले में दोषी शिवनाथ ही है जिसके चलते उसे पर यह कार्यवाही की गई।

बीकापुर में फूड विभाग टीम ने छापा मारकर लिया खोवा का नमूना

अयोध्या। बीकापुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने देर रात कार्रवाई करते हुए कई प्रतिष्ठानों पर जांच की और खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए। टीम ने काली चरन मिष्ठान भंडार तथा वैष्णवी डेयरी के गोदाम से मिठाई और खोवा के सैंपल लिए।बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई एसडीएम बीकापुर श्रेया की शिकायत के बाद की गई। एक दिन पहले एसडीएम श्रेया और सीओ बीकापुर ने क्षेत्र के कई मिष्ठान भंडारों और रेस्टोरेंटों का निरीक्षण किया था, जहां विभिन्न खामियां पाई गई थीं। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नायब तहसीलदार रामखेलावन की मौजूदगी में देर रात दुकानों और गोदामों की जांच कर सैंपलिंग की। अब लिए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पार्टी कार्यालय लोहिया भवन पर शिक्षक सम्मेलन का हुआ आयोजन

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया भवन पर समाजवादी शिक्षक सभा उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय अयोध्या पर शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष दान बहादुर सिंह की अध्यक्षता एवं महासचिव डॉक्टर घनश्याम यादव के संचालन में शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया।जिसमें शिक्षकों एवं शिक्षा व्यवस्था की विभिन्न समस्याओं को लेकर समाधान पर विचार किया गया कार्यक्रम के मुख्य आतिथि मण्डल प्रभारी अयोध्या डावजीतेन्द्र प्रसाद मिश्र मौजूद रहे। शिक्षक सभा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद मिश्र ने कहा आज के समय में शिक्षकों को जागरूक रहने की जरूरत है उन्होंने कहा शिक्षक हीं समाज का मार्गदर्शन करते हैं उन्होंने कहा हमें संगठित होकर जनता को जागरूक करना है और सपा की नीतियों को जन–जन तक पहुंचाने का काम करना है जिला अध्यक्ष दान बहादुर सिंह ने कहा आज भाजपा के शासन मे सबसे ज्यादा काम शिक्षकों से लिया जा रहा है लेकिन इसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है उन्होंने कहा जिस तरह से हर विद्यालय में थम्ब इंप्रेशन से हाजिरी होती है इस तरह शिक्षा भवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी थम्ब इंप्रेशन से हाजिरी होनी चाहिए जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा आज समाज में शिक्षक का सबसे बड़ा योगदान है उन्होंने कहा समाजवादी की सरकार ने ही शिक्षकों का सम्मान किया था और अब यही शिक्षक 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा आज सरकार में सारे पेपर लीक हो रहे हैं सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है उन्होंने कहा आज शिक्षकों को बच्चों के शिक्षा देने के अलावा सरकार के प्रत्येक कामों में लगा दिया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए प्रवक्ता राकेश यादव एडवोकेट ने बताया इस मौके पर शिक्षक सभा जिला अध्यक्ष दान बहादुर सिंह नि.जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, नि.महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, पूर्व प्रमुख राम अचल यादव,महानगर उपाध्यक्ष चौधरी श्रीचंद यादव, महासचिव डॉक्टर घनश्याम यादव, प्रवक्ता राकेश यादव राष्ट्रीय सचिव शिक्षक सभा राम बक्स यादव, विमल सिंह यादव, अवनीश प्रताप सिंह, तहसीलदार सिंह रणधीर सिंह, राम कैलाश यादव, बिलाल अहमद खा, विजय प्रताप सिंह, योगेंद्र कुमार, रंजीत यादव, आकिब खान सनी कुमार, सुरेंद्रनाथ तिवारी, प्रभाकर सिंह, अंबुज मालवीय, सुरेश कुमार दालसिंगार वर्मा, डा वअखिलेश्वर चौबे, श्रीमती सरोज यादव, श्रीमती अपर्णा जायसवाल ,अंसार अहमद, जगन्नाथ यादव, वीरेंद्र गौतम, श्याम प्रकाश वर्मा, राम सिंह, चंद्रकलामल वर्मा, दिनेश कुमार विश्वकर्मा, विकास यादव,, प्रदीप तिवारी राम कैलाश यादव, आदि लोग मौजूद रहे।

पीएम स्वनिधि महोत्सव में डिजिटल लेनदेन करने वाले वेंडरों का हुआ सम्मान

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफल क्रियान्वयन के छह वर्ष पूर्ण होने तथा जून माह में संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत नगर निगम अयोध्या में बुधवार को भव्य "स्वनिधि महोत्सव" का आयोजन किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य अतिथि महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि गरीब के तबके के लोग इस योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार अपना सकते हैं।उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोगों ने इस योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार अपनाया है, उनकी आर्थिक स्थिति में आशातीत सुधार हुआ है। लाभार्थियों को योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए नगर आयुक्त श्री जयेंद्र कुमार बताया कि इसकी अवधि मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। योजना के तहत पात्र रेहड़ी–पटरी व्यवसायियों को चरणबद्ध तरीके से प्रथम ऋण 15 हजार रुपये, द्वितीय ऋण 25 हजार रुपये तथा तृतीय ऋण 50 हजार रुपये तक उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि द्वितीय ऋण का समय पर पूर्ण भुगतान करने वाले वेंडरों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है।अपर नगर आयुक्त एवं परियोजना निदेशक नगरीय विकास अभिकरण डॉ. नागेंद्र नाथ ने बताया कि ऋण की समय पर अदायगी और अधिकाधिक डिजिटल लेनदेन करने वाले लाभार्थियों को कैशबैक प्रोत्साहन भी मिलता है। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की प्रोफाइलिंग कर उन्हें केंद्र सरकार की आठ जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ बनाया जा सके।इस दौरान डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने वाले स्वनिधि लाभार्थी वेंडरों को महापौर ने प्रशस्ति–पत्र देकर सम्मानित किया। योजना के सफल संचालन में योगदान देने वाले नगर निगम के कर्मचारियों को भी प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया गया।कार्यक्रम के दौरान वेंडरों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण (हेल्थ चेक–अप) शिविर आयोजित किया गया।विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पात्र लाभार्थियों के ऋण आवेदन भी स्वीकार किए गये। इस अवसर पर पार्षद अनीता द्विवेदी, शहर मिशन प्रबंधक डूडा बृजेश श्रीवास्तव, सतीश कुमार, बृजेश कुमार,सबीहा, कोमल, गायत्री आदि उपस्थित रहे।

आखिरकार लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद दूसरे दिन ही चला अवैध कोचिंग व लाइब्रेरी पर प्रशासन का शिकंजा

अयोध्या। सोमवार को लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग में अग्निकांड के बाद सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों में डीएम,एसएसपी से लेकर अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने एक साथ कोचिंग तथा लाइब्रेरी पर छापा मारा।मंगलवार को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि संबंधित प्रशासन अवैध रूप से संचालित कोचिंग तथा लाइब्रेरी पर कार्यवाही करेगी।लेकिन दूसरे ही दिन बुधवार को फिर मामला ठंडा बस्ते में चला गया।मंगलवार को लखनऊ कोचिंग अग्निकांड हादसे से अयोध्या शहर में वह भी विकास प्राधिकरण ने आधा दर्जन से अधिक मानक पर खड़े न उतरने के चलते कोचिंग लाइब्रेरी को सील कर दिया था।वहीं बुधवार को ना तो शिक्षा विभाग के अधिकारी शहर में संचालित अवैध रूप से कोचिंग तथा लाइब्रेरी का निरीक्षण करने के लिए बाहर नहीं निकले।जबकि इस समय केवल शहरों में ही देखा जाए तो दर्जनों कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी अग्निशमन विकास प्राधिकरण के मानक पर खड़े नहीं उतर रहे है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस प्रतिष्ठानों के सामने ना तो पर्याप्त सुरक्षा है अधिकतर जगहों पर अन्य सामान यंत्र का अभाव है या फिर कई अग्निशमन यंत्र गोदाम में रखे भी पाए गए उसके अलावा कई कई कोचिंग शहर में ऐसी जगह भी है जहां पर आने–जाने का रास्ता भी एक ही तरफ है और पार्किंग का अभाव है। इस संबंध में स्थानीय लोगों के मन में लखनऊ की घटना को लेकर खाओ दिखाई दे रहा है और एनओसी देने वाले विभागों से एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि संकरी गलियों और रिहायशी इलाकों में संचालित हो रही है।इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है।स्थानीय लोगों व अभिभावकों ने संबंधित विभागों से मांग किया है कि यहां पर संचालित कोचिंग लाइब्रेरी के साथ–साथ माल बड़े–बड़े शॉपिंग माल,अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की भी जांच होनी चाहिए।सवाल यह है कि आखिर कब तक नियमों को दरकिनार कर ऐसे संस्थान संचालित होते रहेंगे और कब प्रशासन प्रभावी अंकुश लगाएगा।

तेज उमस भरी गर्मी के बाद बारिश, गोरखपुर में मौसम खुशनुमा- लोगों को मिली गर्मी से राहत

गोरखपुर, (संवाददाता)। पिछले कई दिनों से तेज उमस भरी गर्मी से परेशान गोरखपुरवासियों को आखिरकार सोमवार दोपहर में राहत मिल गई। अचानक हुई बारिश के बाद शहर का मौसम पूरी तरह बदल गया। बारिश से तापमान में गिरावट आई और उमस खत्म होने से मौसम सुहाना हो गया। लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। पिछले एक सप्ताह से गोरखपुर में उमस भरी गर्मी का कहर था। दिन में चिलचिलाती धूप और रात में उमस के कारण लोगों का हाल बेहाल था। सोमवार को हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। बारिश के बाद तापमान में 4–5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और उमस लगभग खत्म हो गई। गोरखपुर के अलावा आस–पास के देहात क्षेत्र में भी तेज और ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को राहत दिलाई। मौसम सुहाना होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। मौसम विभाग के अनुसार आगे भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे गर्मी से राहत जारी रहेगी। बारिश से पहले अधिकतम तापमान 41–43 डिग्री के आसपास चल रहा था। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट आया है।

पिकअप की टक्कर से व्यापारी की मौत, टहलते समय हुआ हादसा, परिवार में मचा कोहराम

वाराणसी, (संवाददाता)। जिले के बभनी–अंबिकापुर मार्ग पर बीआरसी के समीप दर्दनाक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार की पिकअप ने व्यापारी को टक्कर मार दी, हादसे में व्यापारी की मौत हो गई। वह टहलने के लिए घर से निकला था। सोनभद्र जिले के बभनी थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से व्यापारी गिरवर प्रसाद (47 वर्ष) की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दुर्घटना करने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार बभनी निवासी व्यापारी गिरवर प्रसाद पुत्र विरझू प्रसाद मंगलवार की सुबह करीब 4.45 बजे रोज की तरह टहलने निकले थे। बभनी–अंबिकापुर मार्ग पर बीआरसी के समीप रेणुकूट की ओर जा रही तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना में वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने घायल गिरवर प्रसाद को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। मृतक की दो बेटियां और एक बेटा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी भेज दिया। पुलिस दुर्घटना में शामिल पिकअप वाहन की तलाश कर रही है। प्रभारी निरीक्षक डीपी यादव ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

भाईचारा बनाकर बूथ जीतो चुनाव जीतो में जुटे आईपी रामबृज

प्रयागराज, (संवाददाता)। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के जिला प्रभारी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आईपी रामबृज 264 बारा (सुरक्षित) विधानसभा में भाईचारा बनाकर सेक्टर और बूथ का गठन कर मजबूती के साथ बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान के तहत प्रयत्नशील हैं। रामबृज ने कहा है आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में आजाद समाज पार्टी के बैनर तले अगर एडवोकेट चन्द्रशेखर आजाद का आशीर्वाद मिला तो चुनाव मैदान में उतरा जाएगा और एक एक बूथ जिताकर विधानसभा जिताया जायेगा और विधानसभा 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नगीना सांसद चन्द्रशेखर आजाद को बनाया जायेगा। उक्त बाते यमुनापार की तहसील बारा विकास खण्ड जसरा स्थित ग्रामसभा चिल्ला गोहानी में आयोजित कैडर बैठक में कही। कैडर बैठक को संबोधित करते हुए आईपी रामबृज ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में सेक्टर बूथ बनाकर विधानसभा को चालीस चालीस बूथों का एक एक जोन बनाना है। शैक्षिक रूप से बौद्धिक लोगो को जोन की जिम्मेदारी सौंपकर सेक्टर बूथ का गठन कर बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान को तेज करना है।

रीचौरा क्षेत्र में 70 बिजली के खंभे और 10 ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त

गोरखपुर, (संवाददाता)। अपराह्न करीब तीन बजे आई आंधी और बारिश ने चौरीचौरा क्षेत्र की बिजली व्यवस्था लड़खड़ा गई। आंधी के चलते विभिन्न स्थानों पर पेड़ और टहनियां बिजली के तारों और खंभों पर गिर गईं, जिससे करीब 70 बिजली पोल और 10 ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हो गए। इसके कारण चौरीचौरा सरदारनगर और मुंडेरा बाजार बिजली उपकेंद्रों की आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। चौरीचौरा के अवर अभियंता नवनीत पटेल ने बताया कि गोरखपुर– देवरिया मार्ग स्थित डुमरी खुर्द में निजी स्कूल के पास पेड़ गिरने से छह बिजली के खंभे पर और उस पर लगे ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं, चौरी गांव के सबुनी टोला में 10 केवीए का ट्रांसफॉर्मर पोल टूटने के कारण सड़क पर गिरकर खराब हो गया। इसके अलावा तरकुलहा, परसौनी, चौरी, बंसहिया, शिवपुर महादेवा जंगल, भाऊपुर, केवलाचक, सथरी सहित।

मानीराम स्टेशन पर एनीमोमीटर खराब, ड्राइवर को नहीं मिलेगा अलर्ट

गोरखपुर, (संवाददाता)। आंधी और तूफान आने पर हवा की गति बताने के लिए मानीराम स्टेशन पर लगा एनीमोमीटर (हवा की गति मापने वाला यंत्र) डेढ़ महीने से खराब है। ऐसे में 65 किमी प्रति घंटे से तेज हवा चलने पर ट्रेन ड्राइवर को अलर्ट नहीं मिलेगा। जबकि इस स्पीड से हवा चलने पर ट्रेन न चलाने का निर्देश है। यानी अगर ऐसी स्थिति आती है तो ड्राइवर को खुद की सूझबूझ से निर्णय लेना होगा वरना खतरों के बीच ट्रेन चलती रहेगी। पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेनों के सुरक्षित एवं संरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए चार स्टेशनों पनियहवा, मानीराम, मिहिनपुरवा और मानपुर नगरिया पर एनीमोमीटर लगाए हैं। इनमें मानीराम स्टेशन पर लगा यह यंत्र काम नहीं कर रहा है। रेलवे के जानकारों के मुताबिक, पहले तेज गति से चल रही हवा का मापन चाइनीज संयंत्र से मैनुअल किया जाता था लेकिन अब डिजिटल मशीन लगा दी गई है। स्टेशन भवन पर एरियल और स्टेशन मास्टर के कमरे में डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है जिस पर मापन का ब्यौरा आता रहता है। लेकिन, तीन मई 2026 से यह मशीन खराब हो गई है। एनीमोमीटर से पता चल जाता है कि हवा गति कितनी है। 65 किमी प्रति घंटे से अधिक होने पर स्टेशन मास्टर, लोको पायलट और गार्ड को चेतावनी देते हैं ताकि इस स्थिति में वे सतर्क हो जाएं। 65 किमी प्रति घंटे से तेज हवा चलने पर अगर ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है तो उसे हरी झंडी नहीं मिलती। ट्रेन चल रही है तो लोको पायलट सुरक्षित रेल लाइन पर ले जाकर (जहां सार्प कर्व, कटिंग, ऊंचाई और पुल न हो) ट्रेन रोक देते हैं। कोच कंडक्टर सुरक्षा बलों के सहयोग से सभी कोचों की खिड़कियां खोलवा देते हैं। ताकि ट्रेन पर हवा का दबाव न बन सके और यात्री सुरक्षित हो सकें।

रोप–वे सफर के लिए किराया निर्धारित, न्यूनतम 10 और अधिकतम होगा 50 रुपये

वाराणसी, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश शासन ने वाराणसी रोप–वे परियोजना के लिए किराया दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। यह कदम शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया है। अधिसूचना के अनुसार, यात्रियों के लिए किफायती किराया निर्धारित किया गया है। वाराणसी कैंट, विद्यापीठ, रथयात्रा और गोदौलिया चौक स्टेशनों के बीच यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपये तथा अधिकतम किराया 50 रुपये होगा। वाराणसी कैंट से गोदौलिया चौक तक की पूरी यात्रा का किराया 50 रुपये तय किया गया है। वहीं, विद्यापीठ से रथयात्रा तक की यात्रा के लिए केवल 10 रुपये का शुल्क लगेगा। स्थानीय नागरिकों और नियमित यात्रियों को श्काशी स्मार्ट पासश पर 20 फीसदी की विशेष छूट मिलेगी। इस छूट के साथ कैंट से गोदौलिया चौक तक की यात्रा 40 रुपये में होगी। विद्यापीठ से रथयात्रा तक की यात्रा 8 रुपये में उपलब्ध होगी। निर्धारित किराया दरों में प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 5 फीसदी की वृद्धि की जाएगी। इसे 5 रुपये के निकटतम गुणांक तक पूर्णांकित किया जाएगा। वाराणसी कैंट रोप–वे स्टेशन पर क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। टिकट धारकों के लिए शुरुआती दो घंटे तक सामान रखने की सुविधा निशुल्क होगी। इसके बाद 15 किलोग्राम तक के सामान के लिए 50 रुपये प्रति घंटा शुल्क निर्धारित है।

दक्षिणी कोटवा के ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला, बाल बाल बचे

प्रयागराज, (संवाददाता)। सराय इनायत थाना क्षेत्र के जमुनीपुर गांव में कोटवा प्रधान संकर्षण सिंह उर्फ जयराम सिंह पर रविवार की रात जानलेवा हमला कर दिया गया। पुरानी रंजिश को लेकर पिस्टल से उनके ऊपर चार राउंड फायरिंग की गई। एक गोली कार के शीशे को सुराग करती हुई गोली ड्राइवर के बगल बैठे प्रधान को छूते हुए सीट में जा धंसी। हमले में ग्राम प्रधान बाल बाल बच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिणी कोटवा गांव निवासी संकर्षण सिंह उर्फ जयराम सिंह गांव के प्रधान हैं।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।